statements of condemnation have been repeatedly made by the countries whose nationals have been abducted and by various other international organisations and bodies calling upon the abductors to release the hostages unconditionally. These countries have also been urged to ask Pakistan to use its influence on the abductors to release the hostages. Such efforts will continue.

Proposals by State Governments for setting up industries

421. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the State Governments have submitted proposal before his Ministry to set up industrial units in their respective States;

(b) if so, the number of industries proposed to be set up in different areas in the State of Orissa; and

(c) the details of the proposal submitted by the State Government of Orissa, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) 33 applications were received during 1st January, 1993 to 31st October, 1995 under the provisions of Industries (Development & Regulation) Act, 1951 from undertakings belonging to various State Public Sector and State Industrial Development Corporations for setting up industries in the country.

(b) During the above period one Letter of Intent has been granted to Orissa for setting up industry located at Ganjam.

(c) 6 proposals had been received during the above period from the State Public Sector/State Industrial Development Corporations of Orissa (Ganjam district), Bihar (Patna district) Madhya Pradesh (Guna district) and West Bengal (Nadia & North 24 Parganas districts) for setting up units for the manufacture of various items pertaining to Scheduled Industries viz., Chemicals, Readymade Garments, Sugar, Drugs & Pharmaceuticals and Leather and Leather Goods.

रेलवे विभाग के सामान की चोरी

422. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग में प्रति वर्ष चार करोड़ रुपये से अधिक के सामान की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं की चोरी हुई है; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि इन चोरियों में रेलवे के कर्मचारी/अधिकारी शामिल तो नहीं है, उनके कार्यों की समीक्षा की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये मूल्य का सामान चुराया गया था एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) रेल संपत्ति की चोरी में रेल अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता/मिली भगत पर नियंत्रण रखने के लिए रेल परिसरों और गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है, जब भी किसी रेल कर्मचारी की संलिप्तता अथवा सहापराधिता का मामला प्रकाश में आता है, या तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है अथवा विधि की व्यवस्था के अनुसार न्यायालय में उस पर अभियोग चलाया जाता है।

विवरण

रेलवे के सामान की चोरी के संबंध में विवरण

रेलें	वर्ष	मामलों की सं०	बुक किए गए परेषण	मामलों की संख्या	रेल सामग्री
			(चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)		(चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)
मध्य	1992-93	1001	40,26,391	3612	62,99,306
	1993-94	795	36,93,095	2590	50,89,618
	1994-95	702	1,69,04,483	2266	70,48,192
पूर्व	1992-93	5253	1,71,76,132	23619	1,36,70,351
	1993-94	4123	1,60,56,780	28655	1,34,78,721
	1994-95	3275	1,81,82,971	28565	1,33,99,631
उत्तर	1992-93	1780	71,55,586	42042	95,78,637
	1993-94	1182	82,92,251	30171	82,66,363
	1994-95	1039	75,23,249	20940	84,41,515
पूर्वोत्तर	1992-93	1163	59,56,200	1439	24,77,467
	1993-94	847	40,00,179	1213	19,10,661
	1994-95	644	52,26,498	1059	13,07,417
पूर्वोत्तर सीमा	1992-93	1698	73,20,495	520	23,16,566
	1993-94	1306	1,13,00,194	542	26,94,846
	1994-95	1212	67,68,456	507	16,99,162
दक्षिण	1992-93	2089	63,47,682	5662	43,11,727
	1993-94	1564	40,23,746	6164	23,93,899
	1994-95	987	32,61,388	5470	28,37,646
दक्षिण मध्य	1992-93	647	16,96,061	1179	28,57,763
	1993-94	439	14,81,682	937	20,20,372
	1994-95	296	15,86,437	719	29,23,396
दक्षिण पूर्व	1992-93	1927	1,36,86,462	7003	87,80,735
	1993-94	1816	46,56,294	5392	62,88,429
	1994-95	1228	67,19,359	5353	54,32,494

रेलें	वर्ष	मामलों की सं०	बुक किए गए परेषण (चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)	मामलों की संख्या	रेल सामग्री (चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)
पश्चिम	1992-93	997	47,37,093	2428	22,60,460
	1993-94	730	60,94,282	2242	38,29,654
	1994-95	670	32,72,454	1885	31,42,687
जोड़	1992-93	16555	6,81,02,102	87504	5,25,43,012
	1993-94	12802	5,95,98,503	77906	4,63,71,990
	1994-95	10053	6,94,45,295	66764	4,62,32,140

डा० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशें

423. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को सरकार द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डा० सतीश चन्द्र समिति, जिसने संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने तथा इन परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने की मांगों की जांच की, ने 1990 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार अभी भी इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। चूंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं इसलिए सरकार आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।

Joint Ventures in Operation in the Country

624. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of joint ventures now under operation in the country;

(b) what are their production targets;

(c) whether any other joint ventures have been approved for operation during the current year and next year; and

(d) if so, the particulars of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (d) Details of the joint ventures under operation in the country and their production (data) are not centrally maintained.

During the current year upto September 1995, Government have accorded approvals 975 number of proposals for Joint Ventures involving foreign direct investment of Rs. 11513.8 Crores.

Details of the individual proposals